



आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौती

जैसा कि उस अवधि के इससे पहले आए अन्य आंकड़े दर्शाते रहे हैं, ये आंकड़े भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि देश ने बीच में मिली जरा सी मोहलत का फायदा उठाते हुए हालात काफी हद तक दुरुस्त कर लिए थे। दूसरी लहर ने उसे फिर से बिगाड़ा।

सुमन वर्मा।।

नैशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस (एनएसओ) की ओर से प्रियोरिटी डिवर्फिंग लेवर फोर्स सर्वे दिखता है। उदाहरण के लिए, शाही महिलाओं की स्थिति देखें तो 15 साल और उससे ऊपर की आवादी में बेरोजगारी की जो दर अप्रैल से जून 2020 में 21.1 फीसदी थी, वह जनवरी-मार्च 2021 में घटकर 11.8 फीसदी पर आई और अप्रैल-जून 2021 की अवधि में फिर बढ़कर 14.

जारी हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2021 की तिमाही में शाही इलाकों में 15 साल और उससे ऊपर की आवादी में बेरोजगारी की दर 12.6 फीसदी गई। अगर एक साल पहले की उसी 2020 ही वह अवधि थी, जब कोरोना के अवधि के आंकड़े देखें तो यह दर 20.8 फीसदी थी, नगर अप्रैल-जून से ठीक महेनजर केंद्र सरकार ने सबसे लंबे पहले की तिमाही यानी जनवरी से मार्च देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। 2021 की अवधि में यह दर 8.3 फीसदी स्वामायिक ही उसके कारण बेरोजगारी

दर में अपल्ट्याशित इजाफा हुआ। इसके ठीक एक साल बाद यानी अप्रैल-जून 2021 की अवधि में देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा था।

इसका भी असर जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ा और सासारी अप्रैल से बेरोजगारी में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी देखी गई। मगर ये आंकड़े भारतीय समाज की जिजीविधा का भी संकेत करते हैं। जैसा कि उस अवधि के दृश्यसे पहले लगी और जैसे-जैसे कोरोना से जुड़े प्रतिक्रिया हुते गए, आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई। इसका असर आगे आगे बाले आंकड़ा पर दिखेगा। मगर इसी बीच जल्दी और युक्त युद्ध के रूप में एक नई असाधारण चुनौती अर्थव्यवस्था के सामने आ गई है। बहराहाल, चुनौतियां तो रूप बदल-बदल कर आती हो रही हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के सामने महाराष्ट्र दर को यथासंभव काढ़ू में रखते हुए रोजगार के अधिक से अधिक मोक्ष मुद्द्या कराने की कठिन चुनौती दर्दी हुई है। भीजूदा लालात में इसका जबाब जहाँ लक हो सके सरकारी खर्च के जरिए अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास ही हो सकता है। इसीलिए बजट में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दखला था।



आए अन्य आंकड़े दर्शाते रहे हैं, ये आंकड़े भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि देश ने बीच में मिली जरा सी मोहलत का फायदा उठाते हुए हालात काफी हद तक दुरुस्त कर लिए थे। दूसरी लहर ने उसे फिर से बिगाड़ा। लेकिन इस दूसरी लहर के बाद फिर से स्थितियां सामान्य होने

लगीं और जैसे-जैसे कोरोना से जुड़े अप्रैल-जून 2021 की अवधि में देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा था।

इसका भी असर जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ा और सासारी अप्रैल से बेरोजगारी में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी देखी गई। मगर ये आंकड़े भारतीय समाज की जिजीविधा का भी संकेत करते हैं। जैसा कि उस अवधि के दृश्यसे पहले लगी और जैसे-जैसे कोरोना से जुड़े प्रतिक्रिया हुते गए, आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई। इसका असर आगे आगे बाले आंकड़ा पर दिखेगा। मगर इसी बीच जल्दी और युक्त युद्ध के रूप में एक नई असाधारण चुनौती अर्थव्यवस्था के सामने आ गई है। बहराहाल, चुनौतियां तो रूप बदल-बदल कर आती हो रही हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के सामने महाराष्ट्र दर को यथासंभव काढ़ू में रखते हुए रोजगार के अधिक से अधिक मोक्ष मुद्द्या कराने की कठिन चुनौती दर्दी हुई है। भीजूदा लालात में इसका जबाब जहाँ लक हो सके सरकारी खर्च के जरिए अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास ही हो सकता है। इसीलिए बजट में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दखला था।

मंदिर के दर्शन

अशोक बोहरा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार

कार्तवीय मंदिर

मर्यादा पुरुषोत्तम

श्री राम के अनुज

भाता भरत को

अत्यंत प्रिय था।

यही नहीं इसे

उनकी आत्म

स्थली भी कहा

जाता है। थानकों

के अनुसार भरत जी जब भी अपने ननिहाल केंद्रेय देश जाते तो इस मंदिर के दर्शन जल्द करते। इसके अलावा जब कभी उन्हे मौका मिलता तो भी इस स्थान पर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने आते थे। जास्ती के अनुसार भरत जी जब भी उन्हें काम नहीं करने चाहिए। हिन्दू शास्त्र और धर्मग्रन्थ आज के समय में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले कभी तुम करते थे। ला, आज की पीढ़ी इन्हें अपने जीवन में स्थान देना, इनमें लिखे आदर्शों और सिद्धान्तों को अपने जीवन में डालना भूल गई है लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि ये वैदिक धर्म की धरोहर माने जाने वाले ये शास्त्र अपना औचित्य गवां चुके हैं।



संपादकीय

मौसम बदलने का संकेत

दो राय नहीं कि बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ है जो द्विपक्षीय संबंधों और विश्वास बहाली के नजरिए से ही नहीं, श्रीलंका में भारत की साख मजबूत करने के लिहाज से भी अहम है। पलोटिंग डॉक और डोर्नियर टोही विमान जैसे मुद्दों पर बातचीत 2015 से चल रही थी, पर मामला अधर में था। इस साल उसे मंजूरी मिल गई। भारतीय विदेश मंत्री के दौरे के पहले वहां की विपक्षी पार्टियों एसजेबी और जेबीपी ने सरकार पर यह कहते हुए तीखे हमले किए कि उसने भारत से मिलने वाली आर्थिक मदद के बदले अपने सामुद्रिक और वायु संप्रभुता के साथ समझौता किया है। इसके अलावा कांकेसनथुर्इ बंदरगाह पर हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी भारतीय प्रस्ताव और श्रीलंकाई संविधान में तमिल अल्पसंख्यकों को और अधिक अधिकार दिए जाने संबंधी भारत के अनुरोध पर श्रीलंका ने जिस तरह सकारात्मक संकेत और आश्वासन दिया है वह भी मौसम बदलने का सूचक है। इस बदलते मौसम पर चीन की भी नजदीकी निगाह होगी लेकिन भारतीय राजनय को इसे स्थायी, निरंतरतापूर्ण और दीर्घायु बनाने की कोशिशें लगातार जारी रखनी होंगी।

इसे एक ऐसे कूटनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है, जिसके जरिए भारत ने श्रीलंका में चीन के बीच के

बरक्ष स्थानीय विदेशी और मजबूती में विरासत किया है।

भारत को बढ़ाता

र्ध्दि रिन्डा।।

भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की श्रीलंका यात्रा दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों के नजरिए से काफी सफल रही है। दोनों विदेश मंत्रियों ने आज दर्जन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भारतीय विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि आर्थिक संकट से निपटने में भारत श्रीलंका को निरंतर सहयोग करता रहेगा। द्विपक्षीय संबंधों में राष्ट्राव्यवस्थों या विदेश मंत्रियों के दौरों में समझौतों, सहमतिपत्रों और प्रतिबद्धताओं की ऐसी मुखर अभिव्यक्तियां सामान्य बात मानी जाती हैं, लेकिन इस दौरे को कई कारणों से कुछ विशेष अहमियत दी जा रही है। इसे एक ऐसे कूटनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है, जिसके जरिए भारत में श्रीलंका में चीन के बढ़ते विदेशी व्यापारी और बढ़ोत्तरी आई है।

एततेज दर्ज कराया था कि भारत भूमि से निकट के इन इलाकों में चीन की मौजूदगी उसकी 'चिंताएं बढ़ाने वाली' है। इसके बाव श्रीलंका ने इन परियोजनाओं को निपटत कर दिया था। अब चूंकि यही परियोजनाएं भारत के साहयोग से शुरू हो रही हैं तो भारत की बढ़त को लेकर चर्चाएं रवाचाविक हैं। वेरी भी पिछले कुछ समय में दोनों देशों में संबंध और सहयोग के क्षेत्र में खासी प्रगति आई है। पिछले एक पक्षवाले में पहले श्रीलंका की भारत यात्रा और अब भारतीय विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक सहमतियां कायम की हैं। इनकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बीते एक दशक से भारत के लेकर चर्चा भी ज्यादा समय से श्रीलंका में चीन का वर्चर अधिक रहा है। पर्यावरण 2009 में तमिल अलगाववादी आंदोलन खत्म होने के बाव अपनी खत्म विदेशी रिपब्लिक के लिए श्रीलंका की

ने चीन की ओर कदम बढ़ाया था। कर्ज और मदद की मिली-जुली पेशकशों के बीच 2014 में श्री विनियोग ने श्रीलंका का दौरा भी किया था। उस वक्त भी यह आशाका जाताई गई थी कि यह सब चीन की श्रीलंका को कर्ज के जाल में फँसा कर रणनीतिक फायदे उठाने क